



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
गृह निर्माण अनुमति-पत्र

139

यह अनुमति क्षेत्र 30प्र० नगर नियोजन तथा विकास आदिनियम 1973 की थारा 14 त 15 के अनुमति ही जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूगि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने उत्तरों किसी प्रकार या किसी स्थानीय नियाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारी पर किसी तो कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के नियन्त्रण या स्वामित्व के अधिकारों के पिरान्त कोई प्रभाव न रखेगी।

नियन्त्रित प्रतिवर्णों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री संजय श्रीपाठी व उन्हें अलोक प्रियाठी व उन्हें पिता / पति का नाम श्री दिवेश श्रीपाठी  
मुहल्ला नगल श्रीलेट नं ४५५ सं ६० लिविंग हाउस (एर) वाइ नम्बर श्रीलेट

में नवारो में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के विनियत भवन विवर के अनुसार निर्माण अर्थात् नुस्खा निर्माण करें।

१०। जीर्ण व पुराना वाहा। पृष्ठ भर (भर्व) होटल ०९००  
२०.५.११ संख्या ३०८४२६१।  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद २०

नोट :-

१. यह रवौकृत पत्र केवल पौंछ वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत गान्धीजी ने अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यव भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत विना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की थारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले रो 10 प्रतिशत रांपह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

२. इस अनुमति-पत्र में सइक, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन डीस के पोर्टें को, बारजा, तोहङ्या, सीढ़ी, जाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह जिर से नये निर्माण की स्वीकृति दिये जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक नियमित सूचना द्वारा और शीष कक्ष तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्वक अवश्य जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, मैं कर देगा।

३. मकान निर्माण से यदि नाली के सइक ली घटरी अथवा सइक या नाली के किरी भग : जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण इक गई हो। को सानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक नियमित सूचना द्वारा और शीष कक्ष तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्वक अवश्य जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, मैं कर देगा।

४. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (उपर्युक्त इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

५. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा। जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

६. यदि निर्माण में मास्टर लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनियकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की थारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

त्रिपुरा राज्य विकास प्राधिकरण  
गृह निर्माण अनुमति-पत्र

